पात्र नागरिकों केनाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए व्यापक अभियान चलाएं- रिणवा

एसआईआर-2027 से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में जवाबदेही के साथ पूरे किए जाएं

लखनऊ,(आज समाचार सेवा)। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान अर्हता आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के



लिए अधिकारी व्यापक अभियान चलायें। उक्त निर्देश शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की तैयारियों के संबंध में प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची को त्रुटिरहित, शुद्ध एवं समावेशी बनाने के लिए पूरी गंभीरता से कार्य करते हुए आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर, 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले भावी युवा मतदाताओं से भी अग्रिम आवेदन प्राप्त किए जाएं ताकि उन्हें निर्धारित अर्हता तिथि पर मतदाता बनने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को पूर्ण रूप समावेशी बनाने के लिए राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों का सहयोग लिया जाए। इसके साथ ही विभिन्न शासकीय विभागोंए सामाजिक संगठनों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आरडब्लूए शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से पात्र नागरिकों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने छूटे हुए सभी पात्र नागरिकों के फॉर्म-6 भरवाकर उनको मतदाता सूची में शामिल करने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद एवं विधानसभा स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर 17 नवंबर को प्रकाशित होने वाली आलेख्य मतदाता सूची एवं विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के बाद की पूरक सूचियों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों के साथ बैठक कर आलेख्य मतदाता सूची की जांच की जाये और उसमें आवश्यक सुधारों की पहचान कर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची को जिला निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएं, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से देख सकें और डाउनलोड कर सकें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पदाभिहित स्थलों का चयन एवं पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति समयबद्ध ढंग से की जाए।

त्रुटियों के लिए बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर ईआरओ एवं एईआरओ की होगी जवाबदेही

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली की शुद्धताए विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गंभीर त्रुटि, लापरवाही अथवा दोषपूर्ण कार्य पाए जाने पर संबंधित बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी तथा नियमानुसार उनके मानदेय में कटौती की जाएगी। श्री रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस अवधि में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी, जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाना आवश्यक है।

सभी जनपदों में संचालित होंगे ईवीएम प्रदर्शन केन्द्र

आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के दृष्टिगत प्रदेश में ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने तथा उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी देने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों में ईवीएम प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इन केन्द्रों का संचालन 20 नवंबर 2026 से प्रारम्भ होकर विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की अधिसूचना जारी होने तक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ईवीएम मैनुअल के प्रावधानों एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रदर्शन, प्रशिक्षण तथा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय-तहसील मुख्यालय पर ईवीएम प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इन केन्द्रों के माध्यम से मतदाताओं को बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट की कार्यप्रणाली का व्यावहारिक प्रदर्शन किया जाएगा जिससे वे मतदान की पूरी प्रक्रिया को समझ सकें और वीवीपैट में मुद्रित होने वाली पेपर पर्ची को भी देख सकें।

तिथि 01 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की

हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं-अंगारा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने नए सियासी मोर्चे का ऐलान किया है। दोनों नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा यानि एसपीएम रखा है। इस नये मोर्चे की बाबत प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई है।कोई इसे थर्ड फ्रंट बताकर इसके यूपी की सियासत में बड़ा दखल करार दे रहा है तो कोई इस गठबंधन को तरजीह ही न देने की बात कह रहा है।खैर कुछ भी नतीजे आये लेकिन सियासी पार्टियों को अपने-अपने समीकरण मजबूत रखने खातिर सक्रियता बढ़ाने के लिए मजबूर तो कर ही दिया है।इसी परिप्रेक्ष्य में समाजवादी चिंतक एवं कायस्थ चित्रगुप्त महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव अंगारा ने तो एसपीएम को लेकर कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं।एसपीएम का भी हाल यही है। ये बोलते तो हैं कि बीजेपी को हुकूमत से हटाने और पिछड़ों, शोषितों, किसानों,नौजवानों के हक के लिए मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन सच बिल्कुल इतर है। अंगारा ने कहा कि हम तो इस गठबंधन को बीजेपी की बी टीम मानते हैं,शायद हर समझदार नागरिक भी यही मानेगा। जब पीडीए समाज की एकजुटता में खलल डालोगे तो बीजेपी को तो फायदा होगा ही,जो बीजेपी चाहती है।लेकिन एक बात जरूर जान लीजिए, आज का समय बदल चुका है।

26,720 परिषदीय विद्यालयों में होगा सोशल ऑडिट

प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 20 प्रतिशत परिषदीय विद्यालयों का होगा सोशल ऑडिट

लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश की परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित परिषदीय विद्यालयों के 20 प्रतिशत विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इसके लिए 26,720 परिषदीय विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सोशल ऑडिट निदेशालय, ग्राम्य विकास विभाग और राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी ने सोशल ऑडिट निदेशालय के निदेशक को एमओयू की हस्ताक्षरित प्रति भेजते हुए समझौते के अनुसार अग्रिम देय 50 प्रतिशत धनराशि के हस्तांतरण के लिए बैंक खाते का पूरा विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जिससे धनराशि हस्तांतरण की प्रक्रिया समय से पूरी की जा सके। इस पहल से परिषदीय विद्यालयों में संचालित योजनाओं के वित्तीय और भौतिक पक्षों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सकेगा। सोशल ऑडिट से प्राप्त निष्कर्षों और सुधार संबंधी सुझावों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।एमओयू का मुख्य उद्देश्य समग्र शिक्षा योजना की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रभावशीलता का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना है। इसके अंतर्गत योजना से संबंधित वित्तीय अभिलेखों, वाउचर, अनुदान वितरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। साथ ही योजना के भौतिक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन भी होगा। लाभार्थियों का फील्ड वेरिफिकेशन और सैंपल चेकिंग की जाएगी। सोशल ऑडिट निदेशालय की टीम योजना के क्रियान्वयन में सामने आने वाली कमियों, वित्तीय अनियमितताओं और सुधार संबंधी सुझावों को शामिल करते हुए विस्तृत सोशल ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।समझौते के अनुसार प्रथम पक्ष यानी समग्र शिक्षा की ओर से ऑडिट के लिए आवश्यक सभी फाइलें, रिकॉर्ड, डेटाबेस और दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। सोशल ऑडिट टीम के फील्ड विजिट एवं निरीक्षण के दौरान आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही अनुमोदित शर्तों के अनुसार दूसरे पक्ष को भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। द्वितीय पक्ष यानी सोशल ऑडिट निदेशालय निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष ऑडिट पूरा करेगा। एमओयू हस्ताक्षरित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सोशल ऑडिट के लिए कुल 20 करोड़ 93 लाख 30 हजार 947 रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इसका भुगतान तीन चरणों में होगा। एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद 50 प्रतिशत धनराशि अग्रिम दी जाएगी। चिह्नित विद्यालयों में से 50 प्रतिशत विद्यालयों का सोशल ऑडिट पूरा होने पर 30 प्रतिशत और अंतिम सोशल ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद शेष 20 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

सोशल ऑडिट निदेशालय और राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के बीच एमओयू हस्ताक्षरित

लखनऊ में होगा कौशल दीक्षा समारोह, 21 को आयेंगे पीएम

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को लखनऊ आने वाले हैं। वह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कौशल दीक्षा समारोह में देशभर के आईटीआई के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां तेज हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पड़ताल शुरू कर दिया है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से हर साल देशभर के आईटीआई के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ आयोजन अब तक दिल्ली के विज्ञान भवन में होता रहा है। पहली बार समारोह दिल्ली से बाहर लखनऊ में होने जा रहा है। 21 नवंबर को दोपहर बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम प्रस्तावित है।

बच्चे देश का भविष्य और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर-केशव

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाल दिवस के अवसर पर देश एवं प्रदेश के बच्चों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल, सुखद एवं



सुनहरे भविष्य की कामना की है। श्री मौर्य ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं। आज के बच्चे ही कल के जिम्मेदार नागरिक, कुशल नेतृत्वकर्ता, वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ और राष्ट्र निर्माता बनेंगे। बच्चों की प्रतिभा, जिज्ञासा, रचनात्मकता और ऊर्जा ही विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण और आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। बच्चों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहकर आधुनिक तकनीक, विज्ञान, नवाचार, कौशल विकास और नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ताकि वे बदलते समय की चुनौतियों का सामना करते हुए समाज और देश के विकास में प्रभावी योगदान दे सकें।डबल इंजन सरकार बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नई शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और कौशल विकास के माध्यम से बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के अवसर तैयार किए जा रहे हैंश्री मौर्य ने अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वे बच्चों की प्रतिभा को पहचानें, उन्हें प्रोत्साहित करें और उनके सपनों को साकार करने में सहयोग दें।

अयोध्या-काशी के बाद बीजेपी की मथुरा पर नजर

लखनऊ। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी भाजपा ने मथुरा पर अपनी नजर गड़ा दी है। बीजेपी कान्हा की नगरी से सियासी संदेश देने को तैयार है। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा को लेकर बीजेपी की रणनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 16 और 17 नवंबर को दो दिवसीय चिंतन बैठक करेगा। इसमें पार्टी के करीब तीन दर्जन से ज्यादा भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।17 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन की मजबूती और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा संभव है। भाजपा अयोध्या में श्रीराम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम के बाद अब मथुरा को वैचारिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं के केंद्र में रखने का संदेश देना चाहती है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान का मुद्दा लंबे समय से भाजपा की राजनीति के महत्वपूर्ण विषयों में शामिल है। बता दें, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर दर्शन-पूजन किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या और काशी की तर्ज पर मथुरा के विकास का संकेत दिया था। मुख्यमंत्री के बयान के बाद से ब्रज क्षेत्र में विकास और धार्मिक पर्यटन को लेकर सरकार की भावी योजनाओं पर चर्चा तेज हुई है। अब पार्टी के शीर्ष नेताओं की चिंतन बैठक को राजनीतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जा रहा है। कृष्ण नगरी से भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से को साधने की जुगत लड़ा रही है। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ क्षेत्रीय संगठन, जातीय समीकरण, किसान मुद्दे और चुनावी चुनौतियां बैठक के एजेंडे में रह सकती हैं। पार्टी नेतृत्व के लिए बैठक ब्रज क्षेत्र में संगठन की स्थिति का आकलन करने और चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने का अवसर भी होगी।भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 16 और 17 नवंबर को बैठक की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी पदाधिकारी चिंतन बैठक में शामिल होंगे।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने झूलेलाल घाट और मेहंदी घाट का किया निरीक्षण

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शनिवार को छठ महापर्व के दृष्टिगत महापौर सुषमा खर्कवाल एवं नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ लखनऊ के झूलेलाल घाट एवं मेहंदी घाट का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने घाटों पर स्वच्छता, प्रकाश, पेयजल, चिकित्सा एवं सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री शर्मा ने झूलेलाल घाट पर प्रकाश व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए अतिरिक्त लाइटिंग लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घाटों के साथ ही संपर्क मार्गों, सीढ़ियों एवं आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विद्युत विभाग के अधिकारी निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखें तथा आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार रखें।

भाजपा को 50 सीटें भी मिल जाएं तो हैरानी होगी- अवधेश प्रसाद

लखनऊ। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने एसआईआर, केशव मौर्य के बयान, राहुल गांधी के फोन-टैपिंग के आरोपों और भाजपा के अखिलेश यादव की तुलना जिन्ना से करने पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव के चुनाव की लूट वाले बयान पर अवधेश प्रसाद ने कहा, हमारे नेता की ओर से कही गई बात पूरी तरह से सच है। उनके विचारों से मैं खुद को संबद्ध करते हुए कहता हूं कि भाजपा का यही चेहरा है और पिछले दिनों में देखा गया कि भाजपा वोट के अधिकार को खत्म करना चाहती है, जिसके लिए देश में लगातार संघर्ष चल रहा है। हमारे नेता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इसको बचाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही हैं। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद के बयान 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है को लेकर अवधेश प्रसाद ने कहा, केशव प्रसाद की जमीन नहीं है, वे बुरी तरह से अपने क्षेत्र में चुनाव हार चुके हैं। पार्टी नेताओं की कृपा से उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। पार्टी और सरकार में उनका सम्मान नहीं है। उनको ठीक से कुर्सी भी नहीं मिलती। राहुल गांधी के फोन-टैपिंग के आरोपों पर अवधेश प्रसाद ने कहा, ऐसा संभव है, भाजपा कुछ भी कर सकती है। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा की ओर से अखिलेश यादव के जिन्ना कहने वाले बयान पर अवधेश प्रसाद ने कहा, अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता और जनता का उनके प्रति लगाव देखकर भाजपा घबरा गई है। जैसे-जैसे चुनाव करीब आता जाएगा, भाजपा इतना घबरा जाएगी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आने वाले दिनों में 2027 के चुनाव में भाजपा को अगर 50 सीटें भी मिल जाएं तो आश्चर्य की बात होगी। अखिलेश यादव जैसी लोकप्रियता देश में किसी और नेता की नहीं है। भाजपा की सरकार और नेताओं से प्रदेश के मतदाताओं का भरोसा समाप्त हो चुका है।

बाल दिवस पर योगी का दिखा अलग अंदाज

लखनऊ। बाल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेश के बच्चों को शुभकामनाएं दीं। सीएम योगी ने बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए उनके सुरक्षित बचपन, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बच्चों के प्रति स्नेह और आत्मीयता भरा अंदाज देखने को मिला। नन्हे-मुन्नों के बीच पहुंचे सीएम योगी ने बच्चों को टॉफियां बांटीं, उन्हें दुलारा और प्यार से उनका हालचाल जाना।

भाजपा एसआईआर के ज़रिए दलितों व पिछड़ों से प्रतिशोध ले रही-राजेन्द्र पाल गौतम

लखनऊ। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के दलितों, पिछड़ों और वंचितों ने भाजपा के 400 पार और संविधान बदलने के मंसूबों को रोक दिया। इसलिए भाजपा एसआईआर के ज़रिए दलितों और



कांग्रेस-सपा गठबंधन के सीट बंटवारे पर 17 को होगी वार्ता

पिछड़ों से प्रतिशोध ले रही है। लोग भाजपा की दुर्भावना को समझ गये और दलितों, पिछड़ों, वंचितों ने यह तय कि भाजपा की नफरत की व्यवस्था को भारत में कायम नहीं होने देंगे। उन्होने कहा कि 2019 में भाजपा गठबंधन ने प्रदेश की 80 में से 64 सीटें जीती थीं, जो 2024 में घटकर 36 रह गईं। कांग्रेस-समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 43 सीटें जीतीं। सबसे बड़ा संदेश दलित-आरक्षित सीटों से आया। उत्तर प्रदेश की 80 में से 17 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2019 में भाजपा गठबंधन ने इनमें से 15 सीटें जीती थीं। उन्होने बताया कि सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर 17 नवंबर से बातचीत शुरू होगी। यह बातें उन्होने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा के साथ आयोजित पत्रकारवार्ता में व्यक्त कीं। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या 25.70 करोड़ है और इसके करीब 65 प्रतिशत यानी 167050000 मतदाता होने चाहिए। एसआईआर के बाद अंतिम सूची में सिर्फ़133984792 मतदाता बचे। यानी 33065208 करीब 3.31 करोड़ मतदाता गायब हैं। मुख्यमंत्री जिन 1.27 करोड़ गायब मतदाताओं की बात कर रहे हैं, वह आंकड़ा सिर्फ़पंचायत सूची से तुलना का है। जबकि प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि चुनाव आयोग की एसआईआर की जैसे ही चोरी पकड़ी गयी अब एसआईआर के बाद एसएसआर कराये जाने की बात कही जा रही है, किन्तु यह एसएसआर से अब बच नहीं सकते। संविधान प्रदत्त मताधिकार की रक्षा के लिए 26 नवम्बर संविधान दिवस को कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ मार्च निकालने का निर्णय लिया है।

यूपी में बदलाव की दस्तक,जनता भाजपा का सफाया करने जा रही-अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश



यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की दस्तक है। उत्तर प्रदेश में जनता भाजपा सरकार बदलने जा रही है। जनता भाजपा से बहुत दु:खी और परेशान है। जनता भाजपा का सफाया करने जा रही है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों के आधार पर काम कर रहा है। भविष्य में इंडिया गठबंधन में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहकर दूसरे गठबंधन के लिए बात नहीं करती है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन मिलकर भाजपा को हराने जा रहा है। हमारे कांग्रेस के सम्बंध बहुत अच्छे है। हमने मन बना लिया है कितनी सीटों पर लड़ना है। यह बातें उन्होने शनिवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में व्यक्त कीं। उन्होने कहा कि भाजपा ने कई समाजों के साथ-साथ पूरे देश को गुमराह किया है। जनता सब समझ गयी है। इसीलिए परिवर्तन दिखाई दे रहा है। भाजपा अब हार रही है। 2014 और 2019 में भाजपा यूपी से जीती थी। केन्द्र में उसकी सरकार बनी। भाजपा यूपी में 2024 में हारी है, आज केन्द्र में गठबंधन की सरकार है, सिर्फभाजपा की सरकार नहीं है।

केदारेश्वर के दर्शन के बाद भगवान श्रीराम के दर्शन करने अयोध्या जाऊंगा

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मेरा संकल्प था कि भगवान केदारेश्वर का दर्शन करने के बाद भगवान श्रीराम का दर्शन करने अयोध्या जाऊंगा। सनातन धर्म में जब कोई संकल्प लेता है तो उसी के अनुसार काम करता है। इसीलिए इटावा में केदारेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद प्रभु श्रीराम के दर्शन करने जाने का कार्यक्रम है।

छठ पूजा पर 24 घंटे मिलेगी निर्बाध बिजली, घाट होंगे रोशन

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दीपावली के बाद अब छठ पूजा पर भी 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है। योगी सरकार की प्राथमिकता है कि त्योहार के दौरान गांव से लेकर शहर तक उपभोक्ताओं को सुचारु, सुरक्षित और भरोसेमंद बिजली मिले। पावर कारपोरेशन अलर्ट मोड पर हैं। छठ पूजा घाटों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था करने को कहा गया है, ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं यूपीपीसीएल के अध्यक्ष रणबीर प्रसाद ने छठ पूजा पर प्रदेशवासियों को अनवरत, सुचारु विद्युत आपूर्ति करने को कहा है।

आधुनिक भारत के जिन्ना हैं अखिलेश यादव हिंदुओं को बांटने की करते हैं राजनीतिः भाजपा

लखनऊ। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन के पीछे अखिलेश यादव की जिन्नावादी मानसिकता है। वो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि जिस तरह जिन्ना ने देश को बांटने का काम किया था, उसी तरह अखिलेश यादव अब हिंदू समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। सनातन को गाली देना, लोगों को अपमानित करना और घुसपैठियों से गले मिलना ही अखिलेश यादव की पहचान है। वहीं, बीजेपी प्रवक्ता अंकुश त्रिपाठी ने सपा पर तुष्टीकरण और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2027 में यूपी की जनता अखिलेश यादव को करारा जवाब देगी। अंकुश त्रिपाठी ने कहा कि भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के डीएनए में है। उन्होंने अखिलेश यादव को कलयुग का मारीच बताते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता सपा का सफाया कर देगी। बीजेपी प्रवक्ता ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के अपमान का हिसाब नहीं ले सका, वह प्रदेश की जनता के हक की लड़ाई क्या लड़ेगा ?

यूपी में 38 आईएएस अफसरों के तबादले

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने यूपी में 38 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। तबादला सूची में 5 जिलों के जिलाधिकारी, कई नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी और विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष बदले गए हैं।सबसे बड़ा बदलाव सीतापुर और लखनऊ में हुआ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष रहे प्रथमेश कुमार को अब सीतापुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। उनकी जगह विशेष सचिव, मुख्यमंत्री रहे अनुज सिंह को एलडीए का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सीतापुर के जिलाधिकारी राजगणपति आर को निदेशक, सूडा बनाया गया है। सीतापुर में प्रथमेश कुमार, मुजफ्फरनगर में ग्रेटर नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार सिंह, बिजनौर में विशेष सचिव जोगिंद्र सिंह, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में आपस में अदला-बदली हुई है। महाराजगंज के डीएम गौरव सिंह सौंगरवाल अब सिद्धार्थनगर के डीएम होंगे और सिद्धार्थनगर के डीएम शिवशरणप्पा जीएन अब महाराजगंज के डीएम होंगे। वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल अब गाजियाबाद के नगर आयुक्त होंगे। गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक अब मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। वाराणसी में गोरखपुर के सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी को नया नगर आयुक्त बनाया गया है। सरकारी सूची के मुताबिक अनुज सिंह विशेष सचिव मुख्यमंत्री अपर निदेशक, मंडी परिषद को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण व प्रथमेश कुमार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को जिलाधिकारी, सीतापुर व राजगणपति आर जिलाधिकारी, सीतापुर को निदेशक, सूडा बनाया गया। विक्रमादित्य सिंह मलिक नगर आयुक्त, गाजियाबाद को उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण,हिमांशु नागपाल नगर आयुक्त वाराणसी को नगर आयुक्त गाजियाबाद,शाश्वत त्रिपुरारी मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर को नगर आयुक्त, वाराणसी,अभिषेक कुमार विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स को मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर व संजय कुमार मीणा उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना प्राधिकरण व राजेश कुमार अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना प्राधिकरण को मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या बनाया गया। कृष्ण कुमार सिंह मुख्य विकास अधिकारी अयोध्या को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना प्राधिकरण व डॉ. नितिन मदान अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना प्राधिकरण को संयुक्त प्रबंध निदेशक, जल निगम (नगरीय) व महेंद्र बहादुर सिंह विशेष सचिव, नगर विकास / निदेशक, सूडा निदेशक, सूडा, जल निगम का प्रभार हटाया गया।वंदना त्रिपाठी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा को अपर आयुक्त, सहारनपुर मंडल व प्र